RAJYA SABHA

Thursday, the 25th May, 1995/ 4 Jyaistha, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock. The Deputy Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Protected Water Supply Schemes

*701. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the major failures in the implementation of Protected Water Supply Schemes during the year 1994-95;

(b) whether there is a need to overhaul the Drinking Water Mission;

(c) whether there has been a decelerated pace in this Mission; and

(d) whether any responsibility has been fixed for the non-implementation of the Central Schemes in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) There were no major failures in the implementation of the Rural Drinking Water Programme during 1994-95.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्रीगुंडप्पाकोरवार: उपसभापतिमहोदया, मंत्री जी ने उत्तर दिया है, जी नहीं, जी नहीं। हमारे सामने यह एक बड़ा सवाल है। मैं सरकार को खास कर के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की के लिए 20 हजार करोड़ रुपये रखे हैं। यह बड़ा काम है और महत्वपूर्ण काम है। इस मुल्क में हजारों गांवों में पीने के पानी की किल्लत है। यह गम्भीर समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोशिश की जा रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत है। जो मशीनरी काम कर रही है, वह संतोषजनक नहीं है। अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस काम को करने के लिए बड़े-बड़े अफसर विदेश भेजे जाते हैं। वहां जा कर सेमिनार में हिस्सा लेते हैं और कोर्सिज पाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विदेश भेजे गये अधिकारियों की संख्या क्या है और उन पर अब तक कितना खर्च किया गया है? गांवों में शुद्ध पीने का पानी देने की दिशा में क्या कार्यक्रम है?

श्री उत्तमभाई पटेल: महोदया, यहां से सीधे विदेश नहीं भेजे जाते हैं लेकिन कई देश वहां से खुद के खर्च से हमारी टेक्नीकल सलाह और मार्ग दर्शन के लिए उनको बुलाते हैं तथा अपने खर्च पर उनको बुलाते हैं। पीने के पानी के बारे में हमने जो कदम उठाए हैं आज तक लेकिन बहुत कुछ काम अभी बाकी है। देश के कई ऐसे भाग हैं जिसमें हमको आगे बढ़ना है। यह काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बढ़ावा देने के लिए आगे जा रहे हैं।

श्री गुंडप्पा कोरवार: उपसभापति महोदया, कर्नाटक और खास कर के मेरे जिले जो बीदर, गुलबर्गा, रायचुर और बेल्लारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को यह पूरा पता है कि यह हैदराबाद-कर्नाटक एरिया है जिससे उनके करीब के ताल्लुकात हैं और हमेशा यह अकाल के शिकार होते रहे हैं। जब अकाल पड़ता है तो बावड़ी में पानी नहीं मिलता है, नाली में पानी नहीं मिलता है, नदी में पानी नहीं मिलता है। इतनी मुश्किल हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, दूर-दूर मीलों जा कर वहां से पानी लाना पड़ता है। यह हमारे एरिया की एक गम्भीर समस्या है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में ऐसे कितने गांव हैं जहां पानी की किल्लत है? क्या सरकार ने सर्वे किया है? अगर किया है तो उनकी संख्या कितनी है? साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय में कितने अधिकारी हैं जो विदेश जाकर वापस आए हैं, बड़ी नालेज लेकर आए हैं और इस नालेज का इस्तेमाल इन कामों में कितना हुआ है और पानी के अभाव को दूर करने में उन्होंने क्या काम किया है? 1994-95 के साल में जलापूर्ति कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कर्नाटक में कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्री उत्तमभाई पटेल: उपसभापति महाशया, कर्नाटक में हमने 1994-95 में 5500 गांवों और हैमलेट्स में खर्च तय किया था। इनमें से 4935 में पानी दिया गया है। टोटल यह 89 परसेंट है। लेकिन जो पैसा हमने दिया है वह पूरा नहीं खर्च किया गया है। इसलिए हमने इस काम में राज्य का ध्यान खींचा है कि पैसा पूरा खर्च करके आगे का काम भी अच्छी तरह से करें। अभी तक नये सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में 6086 नयी बस्तियां हैं। बिना जल स्रोत वाले 8 गांव हैं और आंशिक रूप से कवर किए गए हैं 4927, टोटल 4935 हैं। अभी कवर होने से जो बकाया रह गयी हैं बस्तियां वे 6 हजार के लगभग हैं।

SHRI K.R. JAYADEVAPPA: Madam, the Government is spending a huge amount to provide drinking water to the people. This is one of the programmes of the Government. Madam, in the rural areas, some wells were dug by individuals for the benefit of the public. If these wells which were dug for the benefit of the public are demolished for the building of the village Panchayat office, what action the Government proposes to take against such an illegal act? In some villages this is being done. For instance, in my village, the Chairman of the village Panchayat demolished the drinking water well in order to build the village Panchayat office over it. Therefore,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This was a specific question. Your question does not...

SHRI K.R. JAYADEVAPPA: This is a serious question Madam.

THEW DEPUTY CHAIRMAN: It does not arise out of this question. It is very serious, perhaps. But it is not connected with this particular question. I do not think I can ask the Minister to answer this. You can talk to him later on. Shri Ram Ratan Ram.

SHRI K.R. JAYADEVAPPA: Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot ask him to answer this question. I cannot expect him to answer this question. If somebody demolishes a drinking water well to build his Panchayat office, it is wrong. But the Minister cannot answer how it happened and where it happened.

SHRI K.R. JAYADEVAPPA: At least, the reaction of the Minister...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I gave the reaction. He understood.

श्री राम रतन राम: मैडम, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के करीब पांच लाख गांवों में से इस रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत कितने गांवों को अब तक पानी पहुंचा सके हैं? कितने लोगों के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था कर सके हैं? दूसरी बात यह है कि आज हैंड पम्प्स अधिक बनाए जा रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे गांवों में कुएं बनाए जाते थे जिससे पीने के पानी की भी सुविधा होती थी और...

उपसभापति: आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए।

श्री राम रतन राम: स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी हो जाती थी तो क्या रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ कुएं बनाने की भी योजना है?

श्री उत्तमभाई पटेल: सिंचाई के लिए और साथ में पीने का पानी भी मिल जाए ऐसे कुएं हम लोग बनाते हैं।

श्री राम रतन राम: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि पांच लाख गांवों में कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है?

श्री अनन्तराम जायसवाल: क्या माननीय मंत्री जी यह बताएं कि प्रश्नगत योजना के मुख्य-मुख्य बिंदु क्या हैं और प्रत्येक बिंदु से किस हद तक सफलता मिली है, नम्बर एक। दूसरा यह है कि आप जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि प्रदूषित पानी पीने से राजस्थान में नारू रोग होता है, आपकी स्कीम का उस पर क्या असर पड़ा है, कोई कमी आई है या नहीं?

श्री उत्तमभाई पटेल: हम ऐसे रोग की कमी करने के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम उठा रहे हैं और इसमें अभी तक जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसमें गिनी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए और फ्लोराइड नियन्त्रित करने के लिए अत्याधिक संख्या दूर करने के लिए क्षार जल एकत्रीकरण ढांचे के लिए अत्याधिक लौह दूर करने के

लिए 2,924 परियोजनाएं हमने बनाई हैं और कार्यक्रम आगे चल रहे हैं और इसे निपटाने के लिए आर्सेनिक जैसा रोग बंगाल में था तो वहां भी हम खुद गए और वहां देख कर लगा कि इसको रोकना चाहिए तो एक करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी भी दे दी है।

उपसभापति: श्री भूपेन्द्र सिंह मान। आपका स्पेसेफिक सवाल है वह नारू रोग से संबंधित है उसका भी ध्यान रखिए। ...(**व्यवधान**)

श्री अनन्तराम जायसवाल: मैं आपके माध्यम से ...(**व्यवधान**)

उपसभापति: बता दिया उन्होंने आप समझे नहीं होंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल: प्रधान मंत्री से हम रेक्वेस्ट करते हैं...(**व्यवधान**) यह इतना गंभीर मामला है कि प्रधान मंत्री स्वयं इस पर प्रकाश डालें।

उपसभापति: मान साहब बोलिए। I have called Mr. Mann now. I have called Mr. Mann, please.

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदया, एक छोटी सी जानकारी है। इसी प्रश्न से संबंधित है।...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not possible now. I will call you later on. I will call you at a proper time.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान: महोदया, इस वक्त जो गांव में पानी जा रहा है उससे कुछ क्या इन्होंने कभी मंत्री ज़ी ने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, कभी डायरिया की, कभी कॉलरा की या कभी ऐसी कई अन्य बीमारियां आती हैं जैसे जॉन्डिस वगैरह है, तो वह पानी टैस्ट करने के लिए इनके पास क्या है और कितनी बार टैस्ट होता है और अगर गांव में वह बीमारियां फैलती हैं तो उसका इनके पास कोई ईलाज है या किसी को जिम्मेदार ठहराया है या नहीं?

श्री उत्तमभाई पटेल: महोदया, हमने तो सारे देश का दौरा किया था सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का, गांवों में भी गए थे, ऐसी हालत देख करके हर राज्य में ऐसी लैबोरेटरी भी बनाई है और चलती-फिरती लैबोरेटरी भी है और यह काम हम ऐसी तरह से जहां लगता है वहां हम उपाय भी करते है।. . .(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will call one by one, not two people together..

SHRIMATI MIRA DAS: Drinking water is safe if it is free from any contamination. In 1986, the National Drinking Water Mission was started, and, in 1991, it was renamed as "Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission." I want to know from the Prime Minister whether there has been any qualitative change along with the change in the name.

Part (b) of my question is how far the Government has been successful in providing safe drinking water, I mean, water which is free from contamination.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On contamination, the Minister has answered enough.

SHRIMATI MIRA DAS: Madam, this is about safe drinking water.

THE PRIME MINISTER (SHRI P.V. NARASIMHA RAO): The late Rajiv Gandhi had started the Drinking Water Mission. It was he who started six Missions, out of which, the Drinking Water Mission was one. When he was no more, we thought that a programme, a Mission which he had started and which he had concentrated on when he was Prime Minister, should be named after him and continued is that name. This is what has happened Qualitatively, of course, more work has been taken up and more methods which were not available in 1986, have been adopted now. So, there is an inbuilt improvement. His name has been given to the Mission because of his devotion to that particular Mission.

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदया, पिछली बार ग्रामीण क्षेत्र में जल-वितरण की समस्या से संबंधित प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा था कि इस सवाल पर पूरी बहस की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैडम मैंने बहस के लिए एक प्रस्ताव भी सामने रखा है, तो यदि प्रधान मंत्री जी तैयार हों.....

श्री पी०वी० नरसिंह राव: मैं बिल्कुल तैयार हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: तो अगले सप्ताह में कोई दिन तय कर दीजिए जिससे कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार हो जाए क्योंकि यह एक बहत

महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप भी स्वीकार करते हैं और सदन में रोज इस बारे में प्रश्न आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई समय निर्धारित कर दिया जाए।

श्री पी०वी० नरसिंह राव: मैं बिल्कुल तैयार हूं।

उपसभापति: क्योंकि यह सजेशन आया है और प्रधान मंत्री को भी डिस्कस करने में कोई एतराज नहीं है। यह तो टाइम निकालकर चेयरमैन साहब से पूछना पड़ेगा। So, I move on to another question.

राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति संस्थान

*702. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे किसी राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति संस्थान की स्थापना की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में निकट भविष्य में कोई योजना बनाकर एक ऐसा संस्थान स्थापित करेगी; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) आयुर्वेद और ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियां भिन्न हैं। आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्चस्तरीय मानकों के एक मॉडल संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार ने जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राघवजी: महोदया, आयुर्वेद का ज्ञान भारत की एक महान देन है और धरोहर भी है। महोदया, यह उम्मीद की जाती थी स्वतंत्रता मिलने के बाद कि आयुर्वेद की जो उपेक्षा हो रही थी, वह समाप्त होगी, किन्तु 43 वर्ष बीत गए वह उपेक्षा अभी तक बरकरार है इस में शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा आदि के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास अभी तक नहीं हुए हैं। माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया है कि आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्चस्तरीय मानकों के एक मॉडल संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार ने जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संस्थान में उच्च-स्तरीय आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी व्यवस्था है? अगर है तो उसका विवरण क्या है? उसके लिए कितने वैद्य या जो आयुर्वेद के स्नातक हुआ करते हैं, वह कार्यरत हैं?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): We had taken over the Jaipur Ayurvedic College way back in 1976 in order to develop it as the National Institute of Ayurveda. We trained the students in the undergraduate course. There is also a facility for training students in the post-graduate course. I can give details to the hon. Member as to what the courses pursued there. Besides, the Institute gives M.D. degree in Ayurveda in many subjects. There are teaching staff and that institution is looked after by the Central Government.

श्री राघवजी: महोदया, पहली सप्लीमेंटरी में मेरा साफ प्रश्न था कि क्या उच्च-स्तरीय चिकित्सा का प्रबंध वहां पर है? जैसाकि यहां "एम्स" में है वैसा प्रबंध वहां है कि नहीं है? इसका उत्तर आए तो मैं दूसरी सप्लीमेंटरी पूछूं।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Madam, there are two hospitals under the National Institute of Ayurveda. In those hospitals they treat patients under the Ayurvedic system.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it on the same line as the All India Institute of Medical Sciences, but with Ayurvedic systems or it is something different from that?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: They treat the patients in that hospital according to the Ayurvedic system.

श्री राघवजी: महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि दिल्ली में एलोपैथिक पद्धति का जो संस्थान आपने "एम्स" है, उस पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार कितना व्यय करती है और जयपुर में यह जो संस्थान आपने स्थापित किया है, जिसकी जानकारी आपने दी है, उस पर प्रतिवर्ष सरकार कितना व्यय करती है?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: I do not have the information about the All India Institute of Medical Sciences, but I have the information on Jaipur